dence of the Education Minister, the police of Chandigarh shamelessly arrested 89 employees including the President, Secretary and almost all the important office-bearers of the Association. The employees again staged dharna on 27th July, 3rd August and 10th August in support of their demands and for release of their leaders and workers. The police again arrested all those who were peacefully staging dharna. Now the number of arrests has reached 513. The police attacked the hunger-strikers and demolished their camp which was started 80 days before. There is great resentment among the employees of Punjab. The work in the Education Department of Punjab is entirely disturbed and is almost at a standstill. It is highly undemocratic and is undesirable from a Government committed to the restoration of civil liberties and rule of law.

MR. CHAIRMAN: Please try to stick to the text.

SHRI BHAGAT RAM: Only three more sentences. There is hardly any time when prohibitory orders under section 144 are not imposed in Chandigarh to curb the trade union and other democratic activities. This reflects the inefficiency of the administration to deal with the normal situation without the help of the police.

I therefore, demand that all the arrested employees should be immediately and unconditionally released and the Home Minister should make a statement on the shameful act of the police and warn the concerned authorities.

(iii) FACTS REVEALED BY NATIONAL COUNCIL FOR APPLIED ECONOMIC RESEARCH *re.* INDIAN ECONOMY.

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर): सभापति महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो कुछ तथ्य "नवभारत टाइम्स" के दिनांक 14-8-78 के अंक में प्रकाशित हुए हैं और जिनके सम्बन्ध में व्यावहारिक आर्थिक राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद का हवाला दिया गया है, वह अत्यन्त ही गम्भीर एवं आश्चर्यजनक है। साथ ही सरकार के समक्ष एक चेतावनी के रूप में है। समीक्षा में कहा गया है कि जो कदम मंहगाई को रोकने के लिये उठाये जा रहे हैं, उनका लाभ थोक व्यापारी ले रहे हैं या खुदरा दुकानदार, लेकिन उपभोक्ता तक वह लाभ नहीं पहुंच रहा है।

समीक्षा में यह भी कहा गया है कि थोक के भावों में जो गिरावट आती है, वह खुदर भावों में नहीं दिखाई देती। समीक्षा में वितरण व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया गया है तथा इसमें सुधार की अपेक्षा की गई है। कुछ मामलों में स्थिति को मिश्रित भी बताया गया है तथा कुछ मामलों में तुरन्त योग्य कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि औद्योगिक विकास की दर जो पहले 10.4 प्रतिशत थी, वह घटकर इस समय 3.5 प्रतिशत रा गई है। इसे बढ़ाने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं दिखाई पड़ रहा है तथा उद्योग सम्बन्धी नीति का भी विकास पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

सरकार द्वारा मूल्यों को नीचे लाने अथवा उन्हें स्थिर रखने हेतु भी प्रभावी कदम उठाये गये हैं, किन्तु आम जनता को इसका जो लाभ मिलना चाहिये वह कतिपय त्रुटियों से नहीं मिल पा रहा है।

मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि यह मामला गम्भीर आर्थिक चेतावनी के रूप में है, सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट करे कि इस प्रकार आम उपभोक्ताओं के लाभ के लिये तथा औद्योगिक विकास की दर को स्थिर रखने के लिये क्या कदम उठा रही है। मैं चाहूंगा कि संबंधित मंत्री महोदय, इस बारे बारे में वक्तव्य देने की कृपा करें।